ISSN: 2395-7852

International Journal of Advanced Research in Arts, Science, Engineering & Management (IJARASEM)

Volume 11, Issue 4, July 2024

INTERNATIONAL STANDARD SERIAL NUMBER INDIA

IMPACT FACTOR: 7.583

International Journal of Advanced Research in Arts, Science, Engineering & Management (IJARASEM)

| ISSN: 2395-7852 | www.ijarasem.com | Impact Factor: 7.583 |Bimonthly, Peer Reviewed & Referred Journal|

| Volume 11, Issue 4, July 2024 |

समसामयिक विश्व में प्रभुत्व की राजनीति का विश्लेषण

Dr. Brajkishore[1], Jaya Agarwal[2]

Assistant Professor, Department of Political Science, Govt. Girls College, Ajmer, India[1,2]

सार: एक दलीय प्रभुत्व प्रणाली के कारण कोई अन्य विचारधारात्मक गठबंधन या पार्टी उभरकर सामने नहीं आ पायी जो मजबूत व संगठित विपक्ष की भूमिका निभा सके। इस कारण मतदाताओं के पास भी कांग्रेस को समर्थन देने के अतिरिक्त कोई और विकल्प नहीं था। इसके अतिरिक्त एक दलीय प्रभुत्व के कारण प्रशासन की कार्यकुशलता कम हो गयी एवं भ्रष्टाचार में भी वृद्धि हो गयी।

I. परिचय

एक दलीय प्रभुत्व प्रणाली के कारण कोई अन्य विचारधारात्मक गठबंधन या पार्टी उभरकर सामने नहीं आ पायी जो मजबूत व संगठित विपक्ष की भूमिका निभा सके। इस कारण मतदाताओं के पास भी कांग्रेस को समर्थन देने के अतिरिक्त कोई और विकल्प नहीं था। इसके अतिरिक्त एक दलीय प्रभुत्व के कारण प्रशासन की कार्यकुशलता कम हो गयी एवं भ्रष्टाचार में भी वृद्धि हो गयी। अमेरिका और चीन-रूस के गठबंधन के बीच मुक़ाबला तेज़ होता जा रहा है और इस टकराव के नए मोर्चे खुल रहे हैं. हालांकि, चीन और रूस को ये एहसास हो रहा है कि संघर्ष के इस नए दौर में उनका मुक़ाबला कहीं अधिक आक्रामक पश्चिमी देशों से है.[1,2,3]

रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन हाल ही में चीन के दौरे पर गए थे. इसका मक़सद दोनों देशों के सामरिक समझौते को और मज़बूत बनाना था. इस दौरान जिन समझौतों पर दस्तख़त किए गए, उनसे चीन और रूस के रिश्तों के ‘एक नए युग’ का संकेत तो मिलता ही है. पर, इसका बड़ा इशारा अमेरिका के दबदबे को अभूतपूर्व चुनौती देना है. अमेरिका की ताक़त में गिरावट की आशंका ने चीन और रूस को इस उम्मीद में क़रीब ला दिया है कि इससे अमेरिका के पतन की रफ़्तार और तेज़ होगी. आज जब रूस, मौजूदा विश्व व्यवस्था को ढहाना चाहता है, तो वहीं चीन एक आकर्षक नई व्यवस्था का ख़्वाब दिखा रहा है. शीत युद्ध ख़त्म होने के तीन दशक बाद, हेनरी किसिंजर की सलाह के बिल्कुल उलट आज अमेरिका ख़ुद को रूस और चीन के ख़िलाफ़ एक विस्फोटक संघर्ष में उलझा हुआ पा रहा है. ये टकराव एक साथ और अचानक पैदा हुआ है. आज विश्व व्यवस्था इस क़दर निष्क्रिय हो गई है कि आने वाले समय में दुनिया के दो तरह के नियमों में विभाजित होने की तमाम संभावनाएं नज़र आ रही हैं. वैसे तो इसके पीछे बहुध्रुवीय दुनिया का नारा है. लेकिन, आपस में जुड़ने वाली अन्य साझेदारियों का इस्तेमाल एक व्यापक धुरी तैयार करने के लिए किया जा रहा है. जिसमें एक तरफ़ ईरान और उत्तर कोरिया, रूस की सेना को ताक़त देने के लिए हथियारों की आपूर्ति कर रहे हैं. वहीं दूसरी तरफ़, पश्चिमी एशिया में रूस और चीन की मौजूदगी बढ़ रही है. इसके साथ साथ यूरेशिया में व्यापक समीकरण बनते दिख रहे हैं. दुनिया के अलग अलग इलाक़ों में स्थित शक्तियां, जैसे कि पश्चिमी प्रशांत में चीन, यूरोप में रूस और पश्चिमी एशिया में ईरान, अमेरिकी शक्ति के बुनियादी उसूल, यानी अमेरिकी सेना की पूरी दुनिया में घूमने की आज़ादी को मात दे रहे हैं. इन सभी मोर्चों पर एक साथ बढ़ता तनाव अमेरिकी शक्ति को खंड खंड कर रहा है और उसकी सामरिक सैन्य प्रतिक्रिया को जटिल बना रहा है: क्या अमेरिका इन तीनों मोर्चों पर संघर्ष करे या फिर सिर्फ़ एक में जीतने पर ध्यान केंद्रित करे?

आज विश्व व्यवस्था इस क़दर निष्क्रिय हो गई है कि आने वाले समय में दुनिया के दो तरह के नियमों में विभाजित होने की तमाम संभावनाएं नज़र आ रही हैं.
अमेरिका की अहमियत

भय व्याप्त करने में अमेरिका की नाकामी (अफ़ग़ानिस्तान, यूक्रेन, पश्चिमी एशिया और संभावित रूप से ताइवान में) और उसकी छीजती हुई ताक़त बिल्कुल साफ़ नज़र आ रही है. हर बार जब भी अमेरिका मना करता है, तो रूस, इज़राइल, हूती, हिज़्बुल्लाह और ईरान इसके उलट बर्ताव करते हैं. अमेरिका हर साल एक ट्रिलियन डॉलर से ज़्यादा का क़र्ज़ चुकाता है, जो उसके रक्षा बजट से भी ज़्यादा है. ऐसे में अमेरिका के रक्षा उद्योग को दोबारा ताक़तवर बनाने की संभावनाएं मुश्किल नज़र आती हैं. अगले कुछ वर्षों में चीन, रूस, ईरान और उत्तर कोरिया के सामूहिक परमाणु हथियार मिलकर, अमेरिका के एटमी अस्त्रों से दोगुना अधिक हो जाएंगे. इस नई धुरी ने न केवल यूक्रेन और पश्चिमी एशिया के मोर्चों पर पश्चिमी देशों से बेहतर प्रदर्शन किया है. बल्कि, आज ब्रिक्स को सेवाएं देने का मंच बनाकर अब वो इस टकराव को ग्लोबल साउथ में प्रभाव, कारोबार और वाणिज्य [4,5,6]बढ़ाने के संघर्ष के नए मोर्चे और की ओर भी ले जा रहे हैं. चीन के एक जानकार एरिक ली का दावा है कि चीन की ताक़त की तुलना में उसकी महत्वाकांक्षाएं बहुत मामूली हैं. वो कहते हैं कि, ‘दुनिया की तो बात छोड़िए, हम तो एशिया प्रशांत की कमान भी अकेले अपने हाथ में नहीं लेना चाहते हैं.’ एरिक ली ज़ोर देते हुए कहते हैं कि आक्रामकता और दादागीरी वाली महत्वाकांक्षाएं पालना तो चीन की संस्कृति ही नहीं है. वो कहते हैं कि, ‘हम तो बर्बर लोगों को अपने से दूर रखने के लिए महान दीवार बनाते हैं, न कि उनके ऊपर हमला करते हैं.’ चेयरमैन माओ ने 1944 में कहा था कि, ‘चीन को औद्योगीकरण करना होगा और ये काम तो स्वतंत्र उद्यमिता से ही हो सकता है. चीन और अमेरिका के हित आर्थिक और राजनीतिक रूप से एक दूसरे से मिलते जुलते हैं. अमेरिका को डरने की ज़रूरत नहीं है कि हम

लोग सहयोगी नहीं होंगे. हम अमेरिका की बात काटने का जोखिम नहीं ले सकते; हम किसी तरह के संघर्ष का ख़तरा मोल नहीं ले सकते.' लेकिन, माओ के वारिसों ने पहले तो बड़ी कामयाबी से अमेरिका को उसी के खेल यानी पूंजीवाद में हराया और अब वो अमेरिका की अगुवाई वाली विश्व व्यवस्था को चुनौती देने के लिए उसी के भयंकर शत्रु रूस के दोस्त बन गए हैं.
अमेरिका आज भी दुनिया का सबसे ताक़तवर और दोबारा शक्तिशाली बन सकने की क्षमता रखने वाला देश है: 1980 में दुनिया की GDP में अमेरिका की हिस्सेदारी 25 प्रतिशत थी; आज भी है.

तो ये दोहरे नैरेटिव- यानी अमेरिका के पतन और चीन का उभार और ठहराव हमें किस दिशा में ले जाते हैं?

अमेरिका आज भी दुनिया का सबसे ताक़तवर और दोबारा शक्तिशाली बन सकने की क्षमता रखने वाला देश है: 1980 में दुनिया की GDP में अमेरिका की हिस्सेदारी 25 प्रतिशत थी; आज भी है. चीन की अर्थव्यवस्था ने अमेरिका नहीं, बल्कि यूरोप और अन्य देशों की क़ीमत पर विकास किया है. अमेरिका के पास, ईरान से कहीं ज़्यादा तेल के भंडार और क़तर से बड़े गैस के भंडार हैं; आबादी के लिहाज़ से अमेरिका बेहद ऊर्जावान है; दुनिया की सात सबसे बड़ी तकनीकी कंपनियां अमेरिका की हैं. अमेरिका दुनिया का इकलौता देश है, जिसकी सैन्य पहुंच पूरी दुनिया [7,8,9]में है. अमेरिका के पास 800 सैनिक अड्डे, 11 एयरक्राफ्ट कैरियर और 950 अरब डॉलर की विशाल रक़म वाला रक्षा बजट है.

वहीं दूसरी तरफ़ चीन की चमत्कारी तरक़्क़ी आज कई बीमारियों की शिकार है. सुस्त होती विकास दर का लंबा दौर, क़र्ज़ का बढ़ता बोझ (GDP का 287 प्रतिशत), बढ़ती बेरोज़गारी (50 प्रतिशत), बाज़ार और कम्युनिस्ट पार्टी के बीच टकराव, बड़ी तकनीकी कंपनियों के ख़िलाफ़ कार्रवाई, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) की चीन से भगदड़ और सेना में बार बार चलाए जाने वाले सफ़ाई अभियानों में चीन के पतन लक्षण दिख रहे हैं. चीन में बुज़ुर्गों की संख्या, अमेरिका की कुल आबादी से भी ज़्यादा है. आने वाले दशकों में चीन के एक आर्थिक महाशक्ति के बजाय एक नर्सिंग होम में तब्दील होने की आशंकाएं अधिक हैं.

शायद चीन अमेरिका को दबे छुपे शब्दों में ये संदेश भी दे रहा है कि, 'हम सोवियत संघ नहीं हैं. हमारी ताक़त देख लो और समझौता कर लो. तुम प्रशांत में अपने इलाक़े तक सीमित रहो और हम दोनों आपस में मिलकर दुनिया को बांट सकते हैं.

इसीलिए, चीन अपने सामरिक लक्ष्यों में बदलाव कर रहा है और अपने घरेलू और वैश्विक समीकरणों को भी संशोधित कर रहा है. चीन 'छुपकर अपने वक़्त का इंतज़ार करने' की रणनीति की तरफ़ तो नहीं लौट रहा है. बल्कि कुछ हद तक 'ज़ोर शोर और गर्वोक्ति' से पीछे हटने की कवायद में जुटा है. शी जिनपिंग की सबसे बड़ी प्राथमिकता तो भयानक पतन की लगातार की जाने वाली भविष्यवाणियों को ग़लत साबित करने के लिए दूरगामी आर्थिक तरक़्क़ी को दोबारा शुरू करने की है. सुधारों और ज़ोर शोर से बाज़ार की तरफ़ झुकाव रखने वाले मॉडल की जगह लेने के लिए विकास की एक नई परिकल्पना तैयार की गई है. अब एक अधिक सुरक्षित अर्थव्यवस्था बनाने की ख़्वाहिश भी है. इसके अंतर्गत आर्थिक रूप से ज़ोर तो बाज़ार की अगुवाई में आगे बढ़ने पर होगा. लेकिन इस पर मज़बूत सियासी लगाम भी लगी होगी. तो निजी कंपनियों की भूमिका सीमित होगी और डेटा एवं सूचना के अहम प्रवाह, अलीबाबा या टेनसेंट जैसी निजी कंपनियों के बजाय चीन की सरकार के नियंत्रण में होंगे. आदेश दिया गया है कि चीन की कंपनियां और देश के युवाओं को विश्व स्तर के वीडियो गेम तैयार करने पर वक़्त देना कम करें. और, अधिक मज़बूत इरादों के साथ भविष्य की अहम सामरिक तकनीकों में नई नई उपलब्धियां हासिल करने पर अपना ध्यान अधिक लगाएं (टिकटॉक कम और क्वांटम एवं हाइपर सोनिक पर ज़्यादा ज़ोर). चीन की कम्युनिस्ट पार्टी (CCP) को पता है कि उन सामरिक क्षेत्रों में अपनी कमज़ोरियां दूर करने की सख़्त ज़रूरत है, जो भूमंडलीकरण के दूसरे दौर (2.0) को आगे बढ़ाएंगी. यानी आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस (AI), सिंथेटिक बायोलॉजी, उन्नत चिप, क्वांटम इलेक्ट्रिक व्हीकल, अहम खनिज संसाधन वग़ैरह. चीन एक नया दांव भी चल रहा है- 'छोटी छलांगें, बड़ी दुनिया पर जीत'. यानी भविष्य की अहम तकनीकों में अगुवा बनाना और फिर उनका पूरी दुनिया और विशेष रूप से ग्लोबल साउथ में लाभ उठाना अब चीन का नया नुस्खा बन गया है, जिसके ज़रिए वो पश्चिमी देशों के 'छोटे क्षेत्र, ऊंची दीवार' की रणनीति को जवाब दे रही है (इस रणनीति के तहत पश्चिमी देश विशेष तकनीकों को केवल गिने चुने देशों के बीच साझा करके उसका लाभ उठाने की कोशिश कर रहे हैं).

आज जब जंग के नए नए मोर्चे खुल रहे हैं, तो ये टकराव और तेज़ होता जा रहा है. पिछले चरण (छुपकर बारी का इंतज़ार करो) के दौरान चीन आगे निकल गया, क्योंकि अमेरिका का ध्यान इस तरफ़ नहीं था. चीन को एहसास है कि इस नए संघर्ष में उसका मुक़ाबला एक जागरूक और कहीं ज़्यादा आक्रामक पश्चिमी देशों से है.

शी जिनपिंग कहा करते थे कि, 'प्रशांत क्षेत्र इतना बड़ा है कि उसमें हम दोनों के लिए पर्याप्त गुंजाइश है'. सैन फ्रांसिस्को में जिनपिंग ने कहा था कि, 'धरती इतनी विशाल है कि हम दोनों के लिए पर्याप्त है.' चीन की महत्वाकाक्षाएं फैल रही हैं. अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था को बदलने की उसकी ख़्वाहिश भी ज़ोर पकड़ रही है. शायद चीन अमेरिका को दबे छुपे शब्दों में ये संदेश भी दे रहा है कि, 'हम सोवियत संघ नहीं हैं. हमारी ताक़त देख लो और समझौता कर लो. तुम प्रशांत में अपने इलाक़े तक सीमित रहो और हम दोनों आपस में मिलकर दुनिया को बांट सकते हैं.' आने वाले समय में इस संघर्ष के दो ही नतीजे निकल सकते हैं: व्यापक युद्ध या अस्थिर शांति. इसका सबसे बड़ा इम्तिहान शायद ताइवान होगा.

भारत को भी अपने प्रयासों में तेज़ी लानी होगी. अगर हम ऐसा नहीं करते, या दुनिया के व्यापक मंचों जैसे कि ब्रिक्स और ग्लोबल साउथ में अगर हम चीन को मात नहीं दे सकते, तो इसका नतीजा एकध्रुवीय एशिया के रूप में सामने आ सकता है.[10,11,12]

II. विचार-विमर्श

पिछले दशक में चीन दुनिया के प्रमुख मसलों को सुलझाने के लिए आगे आया है. यह रणनीति चीन को अमेरिका के बरअक्स स्थापित कर रही है, और उसे अफ्रीका व एशिया के उन देशों का समर्थन भी दिला रही है जो अमेरिका और पश्चिम से सशंकित रहते हैं.

पिछले दशक में चीन सिर्फ बड़ी अर्थव्यवस्था के लिए नहीं बल्कि दुनिया के प्रमुख मसलों को सुलझाने के लिए पहचाना जाने लगा है. हाल के वर्षों में चीन अंतरराष्ट्रीय मसलों पर मध्यस्थता को लेकर अत्यधिक सक्रिय हो गया है. अफगानिस्तान, बांग्लादेश, सीरिया और इजरायल जैसे देशों में संघर्ष को रोकने या उसका हल खोजने के लिए चीन आगे आ रहा है.

आखिर क्यों चीन बतौर मध्यस्थ एक बड़ी शक्ति के रूप में उभर रहा है?
साल 2012 में चीन केवल तीन अंतरराष्ट्रीय मसलों पर मध्यस्थता कर रहा था, 2017 में यह संख्या नौ हो गई. ध्यान रहे 2012 में शी जिनपिंग चीन की कम्युनिस्ट पार्टी (सीसीपी) के महासचिव बने थे, और 2013 में चीन के राष्ट्राध्यक्ष. चीन की मध्यस्थता गतिविधियों में सक्रियता साल 2013 से शुरू होती है. इसी वर्ष बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव (बीआरआई) शुरू हुआ था. इससे पहले चीन अंतरराष्ट्रीय मसलों पर मध्यस्थता के लिए अपेक्षाकृत अनिच्छुक दिखाई देता था.

बीआरआई के साथ चीजें बदल गईं. चीन न सिर्फ़ मध्यस्थता प्रयासों पर अधिक ध्यान देने लगा, यह अपनी गतिविधियों को मीडिया के माध्यम से सक्रिय रूप से प्रचारित करने लगा. गौरतलब है कि चीन ने अपने मध्यस्थता प्रयासों को दक्षिण एशिया, मध्य पूर्व और पूर्वी अफ्रीका पर केंद्रित किया है – जो बीआरआई के लिए रणनीतिक-आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं.

चीन यह भूमिका इसलिए भी निभा पा रहा है क्योंकि वह एक शक्तिशाली अर्थव्यवस्था बन चुका है. चीन की विशाल अर्थव्यवस्था उसे विश्व स्तर पर प्रभुत्ववान बनाती है. चूँकि उसका तमाम देशों में निवेश है, उसकी आर्थिक शक्ति उसे इन देशों के बीच मध्यस्थता के लिए सक्षम बनाती है.

फिलिस्तीन के विभिन्न गुटों के बीच चीन ने किस समझौते को अंजाम दिया? इसका क्या भविष्य है?
इजरायल-फिलिस्तीन के बीच जारी हालिया संघर्ष में जहां पश्चिम की सरकारों ने एकतरफा रुख अपनाते हुए इजरायल के साथ एकजुटता दिखाई है, वहीं चीन ने फिलिस्तीन को संगठित करने का प्रयास किया है. चीन के प्रयासों से इजरायल के प्रतिद्वंद्वी फतह और हमास ने संयुक्त रूप से गाजा और वेस्ट बैंक में अंतरिम सरकार चलाने पर राज़ी हुए हैं. बता दें कि चीन फिलिस्तीनी मुद्दे के प्रति सहानुभूति रखता रहा है और द्विराष्ट्र सिद्धांत का समर्थक रहा है.

पिछले सप्ताह फिलिस्तीनी गुटों ने एक 'राष्ट्रीय एकता' समझौते पर हस्ताक्षर किया, जिसका उद्देश्य इजरायल से युद्ध समाप्त होने के बाद गाजा पर फिलिस्तीनी नियंत्रण बनाए रखना है. चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने कहा था कि तीन दिनों की गहन वार्ता के बाद मंगलवार (22 जुलाई, 2023) को फिलिस्तीन के अलग-अलग धड़ों के प्रतिनिधि साथ मिलकर सरकार चलाने को तैयार हुए हैं. इस समझौते पर पुराने प्रतिद्वंद्वी हमास और फतह के साथ-साथ 12 अन्य फिलिस्तीनी समूहों ने भी हस्ताक्षर किया है. इन दोनों प्रतिद्वंद्वियों का एक मंच पर आना ऐतिहासिक है, और चीन की कूटनीतिक उपलब्धि भी.

इस साल अप्रैल में भी चीन ने फतह और हमास की मेजबानी की थी. वार्ता के नवीनतम दौर में हमास के राजनीतिक गुट के प्रमुख इस्माइल हनीयेह और फतह के उप प्रमुख महमूद अल-अलौल शामिल थे.

हालांकि, इजरायल फिलिस्तीनों धड़ों के बीच करार से नाखुश है. वह गाजा पर शासन करने में हमास की भूमिका का कड़ा विरोध करता है. हमास के साथ सहयोग करने के लिए फतह प्रमुख और फिलिस्तीनी प्राधिकरण के अध्यक्ष महमूद अब्बास पर निशाना साधते हुए इजरायल के विदेश मंत्री इजरायल काट्ज़ ने कहा कि संघर्ष समाप्त होने के बाद गाजा पर इजरायल के अलावा किसी का नियंत्रण नहीं होगा.

दिलचस्प है कि समझौते को एक सप्ताह ही बीता है और हमास के नेता इस्माइल हनीयेह की ईरान की राजधानी तेहरान में हत्या (30 जुलाई) कर दी गई है. इस हमले की किसी ने जिम्मेदारी नहीं ली है. लेकिन हमास इसे यहूदी हमला बता रहा है. ईरान के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि हनीयेह का बलिदान बेकार नहीं जाएगा. वहीं अयातुल्ला अली खामेनेई ने कहा कि हनीयेह की हत्या का बदला लेना तेहरान का कर्तव्य है.

यह चीन के सामने चुनौती है कि हमास के प्रमुख नेता की हत्या के बाद वह हालिया समझौते को कैसे साधता है.
सऊदी-ईरान के बीच समझौता और चीन की कूटनीतिक सफलता [13,14,15]

पिछले साल मार्च में जब चीन के प्रयासों से मध्य पूर्व के दो प्रतिद्वंद्वी देश ईरान और सऊदी अरब ने दोस्ती का हाथ बढ़ाते हुए कूटनीतिक रिश्ते बहाल करने की अप्रत्याशित घोषणा की, तो पूरी दुनिया विशेषकर पश्चिम चकित रह गया था. अमेरिका लंबे समय से मध्य पूर्व में अपनी राजनीतिक शक्ति और प्रभाव बनाए हुए है. लेकिन इस क्षेत्र में चीन की बढ़ती पैठ इस गणित को बदल रही है. 10 मार्च, 2023 को सऊदी अरब और ईरान ने चीन की मध्यस्थता से संबंधों के सामान्य होने की घोषणा की थी. एक संयुक्त त्रिपक्षीय बयान में कहा गया था कि सऊदी अरब और इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान के बीच समझौता हो गया है. बयान में दोनों देशों ने राजनयिक संबंध बहाल करने और कुछ ही महीनों में दूतावासों को फिर से खोलने की बात कही थी.

सामरिक दृष्टि से यह एक मास्टर स्ट्रोक था. खाड़ी के दुश्मन देशों को एक दूसरे के करीब लाकर चीन यह दिखाने में कामयाब रहा कि वह दुनिया के सबसे अशांत क्षेत्रों में भी संतुलन बहाल कर सकता है, जबकि अमेरिका इन दोनों शक्तियों को एकसाथ लाने में विफल रहा था. सऊदी और ईरान के समझौते को अंजाम देकर चीन ने अपने लिए दो महत्वपूर्ण तेल उत्पादकों का समर्थन भी हासिल कर लिया. रियाद और तेहरान के बीच शांति समझौता खाड़ी में चीन के बढ़ते रणनीतिक और आर्थिक हितों को साधता है.

चीन पिछले दशक में किन संघर्षरत देशों को समझौते के मंच पर लेकर गया है?
साल 2013 में बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव (बीआरआई) की शुरुआत के साथ चीन अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता के मामलों में अधिक सक्रिय होता है. हालांकि प्रयास पहले भी जारी थे, लेकिन छोटे स्तर पर. पिछले एक दशक में चीन को सीरिया में गृह युद्ध, इजरायल-फिलिस्तीन संघर्ष, रोहिंग्या लोगों को लेकर बांग्लादेश-म्यांमार विवाद, अफगानिस्तान-पाकिस्तान विवाद, कोरिया और दक्षिण सूडान विवाद की मध्यस्थता करते देखा गया है. इससे पहले चीन नेपाल, ज़िम्बाब्वे और रवांडा के घरेलू राजनीतिक संघर्षों में भी मध्यस्थता कर चुका है.

चीन की मध्यस्थता अमेरिका की मध्यस्थता से किस तरह भिन्न है और इसका वैश्विक व्यवस्था पर क्या प्रभाव दिखाई दे रहा है?
सऊदी-ईरान समझौते का ही उदाहरण लेते हैं. चीन ने जो किया वह स्पष्ट रूप से अमेरिकी तरीके के विपरीत था, जहां 'बड़े लोग' (अर्थात वाशिंगटन) छोटे देशों पर अपनी इच्छा थोपते हैं. चीन का रवैया शांति बहाली के नाम पर दूसरे देशों की सरकार चलाने का नहीं रहा है- जैसे अमेरिका अफगानिस्तान समेत अन्य देशों में करता रहा है. चीन खुद को एक ऐसी शक्ति के रूप में स्थापित करना चाहता है, जो एक शांतिपूर्ण, बहुपक्षीय विश्व व्यवस्था चाहता है, न किसी एक देश का आधिपत्य.

यह रणनीति चीन को अमेरिका के बरअक्स स्थापित कर रही है, और चीन को अफ्रीका व एशिया के उन तमाम देशों का समर्थन भी दिला रही है जो अमेरिका और पश्चिम से सशंकित रहते हैं.

III. परिणाम

दुनिया में भारतवंशियों का बढ़ता प्रभुत्व
प्रवासी भारतीयों और भारतवंशियों का प्रभुत्व दिन-प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है. प्रवासियों के मामले में सबसे ज्यादा लगभग 1.8 करोड़ भारतीय प्रवासी दूसरे देशों में रहते हैं. भारतीय प्रवासियों का शीर्ष गंतव्य अमेरिका है. दशकों पहले ब्रिटेन के तत्कालीन प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल ने भारतीयों की नेतृत्व और प्रशासनिक क्षमता का उपहास उड़ाते हुए कहा था कि भारतीयों में नेतृत्व क्षमता नहीं होती है. लेकिन भारत की आजादी के 75 वर्ष बाद आज उसी ब्रिटेन के प्रशासन की डोर एक भारतीय मूल के राजनेता के हाथों में है. ऋषि सुनक का ब्रिटेन का प्रधानमंत्री बनना एक ऐतिहासिक घटना है, जिससे सभी भारतीय गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं.

सुनक से पहले भी कई भारतवंशी विभिन्न देशों के शासनाध्यक्ष बन चुके हैं, लेकिन भारतीय मूल के व्यक्ति का ब्रिटेन जैसे प्रमुख देश का प्रधानमंत्री बनना बहुत विशिष्ट है. हर बार भारतवंशियों की अंतरराष्ट्रीय पटल पर उल्लेखनीय सफलताएं भारतीयों की प्रतिभा के बढ़ते प्रभुत्व को सुदृढ़ करती हैं. भारतवंशी हर दिशा और विधा में धीरे-धीरे अपना प्रभुत्व बनाते जा रहे हैं.

दस विभिन्न देशों में कुल 31 बार भारतीय मूल के प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति रहे हैं. कई भारतीय वैश्विक स्तर पर महत्वपूर्ण राजनीतिक पदों पर हैं. अमेरिका की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस, स्टेट सीनेटर यास्मीन ट्रूडो विश्व प्रसिद्ध नाम हैं. कनाडा जैसे प्रमुख देश में पिछले वर्ष के चुनाव में 17 भारतवंशी चुनाव जीतकर राजनीति में सक्रिय हैं.[16,17,18]

वर्ष 2008 में छपे इकोनॉमिक टाइम्स के रिपोर्ट के अनुसार, अमेरिका के विश्व प्रसिद्ध वैमानिकी और अंतरिक्ष संस्था नासा में 36 प्रतिशत वैज्ञानिक हैं. अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ फिजीशियंस ऑफ इंडियन ओरिजिन के 2019 के आंकड़ों के अनुसार अमेरिका के 29.5 प्रतिशत चिकित्सक भारतीय मूल के हैं. यही स्थिति व्यवसाय क्षेत्र में भी है. जहां भारतीय मूल के व्यवसायियों द्वारा स्थापित व्यवसाय अग्रणी हो रहा है, वहीं विश्व की बड़ी कंपनियां भारतीय मूल के पेशेवरों को सर्वोच्च पदों पर नियुक्त कर रही हैं.

| ISSN: 2395-7852 | www.ijarasem.com | Impact Factor: 7.583 |Bimonthly, Peer Reviewed & Referred Journal|

| Volume 11, Issue 4, July 2024 |

गल्फ टुडे की एक रिपोर्ट के अनुसार, फॉर्च्यून 500 कंपनियों में से 30 प्रतिशत में भारतीय सीईओ हैं और अमेरिका की सिलिकॉन वैली में नियुक्त इंजीनियरों में एक तिहाई भारत से हैं. ऐसे परिप्रेक्ष्य में भारतवंशियों के व्यवसाय और तकनीक में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बढ़ते प्रभुत्व की विवेचना आवश्यक हो जाती है. भारतीय मूल के अरबपति व्यवसायियों की फेहरिस्त दिन-प्रतिदिन बढ़ती जा रही है.

भारतीय मूल के विश्व प्रसिद्ध उद्योगपतियों में आर्सेलर-मित्तल के लक्ष्मी मित्तल, जेडस्केलर के जय चौधरी, सन माइक्रोसिस्टम के पूर्व सहसंस्थापक विनोद खोसला, वेदांता रिसोर्सेज के अनिल अग्रवाल, सिम्फनी टेक्नोलॉजी ग्रुप के संस्थापक रोमेश वाधवानी शामिल हैं, साथ ही हजारों अप्रवासी भारतीय विदेशों में सफलतापूर्वक अपने व्यवसाय संचालित कर रहे हैं. जहां भारतीय मूल के अरबपति उद्योगपतियों की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है, वहीं फेहरिस्त में पहले से स्थापित उद्योगपतियों की नेट वर्थ और बाजार मूल्यांकन में तेज वृद्धि हो रही है.
उदाहरण के तौर पर, विनोद खोसला का नेट वर्थ 2020 के 2.3 अरब अमेरिकी डॉलर से दो वर्ष में बढ़कर 5.3 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया है, वहीं रोमेश वाधवानी की कुल संपत्ति 2020 के 3.4 अरब डॉलर से बढ़कर 5.1 डॉलर तक पहुंच चुकी है. विदेशों में बसे भारतीय मूल के पेशेवरों और आम उद्यमियों की औसत आय निरंतर बढ़ रही हैं.

ग्लोबल इंडियन टाइम्स के अक्टूबर, 2021 में प्रकाशित एक अध्ययन के अनुसार, अमेरिका की 44 प्रमुख कंपनियों के सीइओ भारतीय हैं. आइटी क्षेत्र की सबसे बड़ी कंपनी माइक्रोसॉफ्ट के सीइओ सत्या नडेला और प्रसिद्ध इंटरनेट कंपनी अल्फाबेट के सुंदर पिचाई भी भारतीय मूल के ही हैं. सॉफ्टवेयर कंपनी एडोब के शांतनु नारायण, आईबीएम के अरविंद कृष्ण, एलएमवेयर के रंगराजन रघुराम, अरिस्टा नेटवर्क की जयश्री उल्लाल, मास्टर कार्ड के अजयपाल सिंह बग्गा सहित अनेक भारतीय मूल के पेशेवर लोकप्रिय आइटी और तकनीकी कंपनियों का संचालन कर रहे हैं.

पहले भारतीय पेशेवरों को तकनीकी व्यवसाय तक सीमित माना जाता था, लेकिन बार्कलेज के सीएस वेंकटकृष्णन, खुदरा लक्जरी और आभूषण की प्रसिद्ध कंपनी चैनल की लीना नायर इत्यादि गैर आइटी क्षेत्र में भारतीय मूल के पेशेवर प्रभुत्व स्थापित कर रहे हैं. गल्फ टुडे की रिपोर्ट के अनुसार, पूरी दुनिया के लगभग 10 फीसदी उच्च तकनीकी कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारी भारतीय मूल के हैं.

उदाहरण के तौर पर, अभी पिछले वर्ष नवंबर में प्रसिद्ध सोशल मीडिया संस्था ट्विटर ने भारतीय मूल के पराग अग्रवाल को अपना सीइओ नियुक्त किया था. अभी सितंबर महीने में स्टारबक्स कॉरपोरेशन ने लक्ष्मण नरसिम्हन को अपना अगला मुख्य कार्यकारी अधिकारी नामित किया है. नरसिम्हन पहले रेकिट बेंकिजर के सीईओ थे.

प्रत्यक्ष तौर पर प्रवासी भारतीयों और भारतवंशियों का प्रभुत्व दिन-प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है. प्रवासियों के मामले में सबसे ज्यादा लगभग 1.8 करोड़ भारतीय प्रवासी दूसरे देशों में रहते हैं. भारतीय प्रवासियों का शीर्ष गंतव्य अमेरिका है. भारतीय अमेरिका के सबसे धनी और सफल अप्रवासी समूह हैं. अंतरराष्ट्रीय उद्योग विशेषज्ञ भारतीय उद्यमिता को विश्व के आर्थिक विकास का महत्वपूर्ण इंजन बताते हैं.

भारतीयों को किसी भी समाज या समूह में एकीकृत करने की कला बेहतर आती है. उन्हें तकनीक की अच्छी समझ होती है, जिसका उपयोग हर क्षेत्र को बेहतर बनाने में किया जा रहा है. भारतीयों के विश्व स्तर पर बढ़ते प्रभुत्व में अच्छी अंग्रेजी बोलना भी बड़ा कारण है. भारतीय अपने अनुशासन, कर्मठता, बेहतर रणनीति के लिए जाने जाते हैं. आज ऋषि सुनक को विपरीत राजनीतिक और आर्थिक परिदृश्य में ही ब्रिटेन का प्रधानमंत्री बनाया गया है, क्योंकि हम भारतीयों के कौशल पर विश्व समुदाय का भरोसा लगातार बढ़ता जा रहा है.

भारत सरकार भारतवंशियों और प्रवासी भारतीयों को देश से जोड़े रखने के लिए आवश्यक कदम उठाती रहती है. जैसे वज्र योजना की तर्ज पर आवर्तन कार्यक्रम के अंतर्गत शीर्ष एनआरआई वैज्ञानिक, इंजीनियर, डॉक्टर, प्रबंधक और पेशेवरों की दक्षता और विशेषज्ञता का बेहतर उपयोग विभिन्न सरकारी, गैर सरकारी और शिक्षण संस्थानों में किया जा सकता है.

प्रवासी भारतीयों को देश में अधिकाधिक निवेश करने के लिए बेहतर माहौल बना कर प्रोत्साहित किया जाना चाहिए. अमेरिका के वेटेरंस एडमिनिस्ट्रेशन की तर्ज पर एनआरआई की मदद के लिए एक समर्पित विभाग स्थापित करने से प्रवासी भारतीयों को सहूलियत होगी. बेहतर प्रयास से देश के अंदर और देश से बाहर रहने वाले भारतीयों में पारस्परिक मदद का माहौल तैयार कर भारतवंशियो के बढ़ते प्रभाव का सदुपयोग किया जा सकता है.[18,19]

IV. निष्कर्ष

यह सत्य है कि एकल पार्टी प्रभुत्व प्रणाली का राजनीतिक लोकतांत्रिक प्रवृत्ति पर विपरीत प्रभाव पड़ता है तथा प्रभूत्व प्राप्त दल विपक्षी पार्टियों की आलोचना की परवाह न करके मनमाने ढंग से शासन चलाने लगता है व लोकतंत्र को तानाशाही शासन में बदलने

की संभावना विकसित होती है, परन्तु हमारे देश में ऐसा नहीं हुआ। पहले तीन आम चुनावों में कांग्रेस के प्रभुत्व का भारतीय राजनीति पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ा। इसने भारतीय राजनीति के लोकतांत्रिक चरित्र को सुदृढ़ बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह किया।[20]

संदर्भ

1. लेफ्टविच 2015 , पृ. 68.
2. ^ हेग और हैरोप 2013 , पृष्ठ 1।
3. ↑ हैमरलैंड 1985 , पृ. 8.
4. ^ ब्रैडी 2017 , पृ. 47.
5. ^ हॉक्सवर्थ और कोगन 2013 , पृष्ठ 299।
6. ↑ टेलर 2012 , पृ. 130.
7. ^ ब्लैंटन और केगली 2016 , पृष्ठ 199।
8. ^ काबाशिमा और व्हाइट III 1986
9. ^ बुहलर, सी.एफ., एड. 1961 [1941]। दार्शनिकों के कथन और कथन.लंदन : अर्ली इंग्लिश टेक्स्ट सोसाइटी, मूल श्रृंखला संख्या 211 5 सितंबर 2016 को वेबैक मशीनपर .
10. ↑ लुईस और शॉर्ट 1879 , ऑफ़लाइन।
11. ^ लिडेल, जॉर्ज हेनरी; स्कॉट, रॉबर्ट। "ए ग्रीक-इंग्लिश लेक्सिकन" । पर्सियस डिजिटल लाइब्रेरी । टफ्ट्स लाइब्रेरी। मूल से 24 सितम्बर 2015 को। 19 फरवरी 2016 को लिया गया।
12. ^ लासवेल 1963 .
13. ↑ ए बी यहाँ जाएँ: ईस्टन 1981 .
14. ↑ लेनिन 1965 .
15. ^ बिस्मार्क रैहस्टाग स्कोच द्वारा, 29 जनवरी, 1886, में: बिस्मार्क, द कलेक्टेड वर्क्स । फ्रेडरिकश्रुहर संस्करण, खंड 13: भाषण। विल्हेम शूस्लर समुद्र तट, बर्लिन 1930, पृष्ठ 177।
16. ↑ क्रिक 1972 .
17. ^ लेफ्टविच 2004 .
18. ^ लेफ्टविच 2004 , पृ. 14-15.
19. ↑ लेफ्टविच 2004 , पृ. 23.
20. ↑ लेफ्टविच 2004 , पृ. 119.

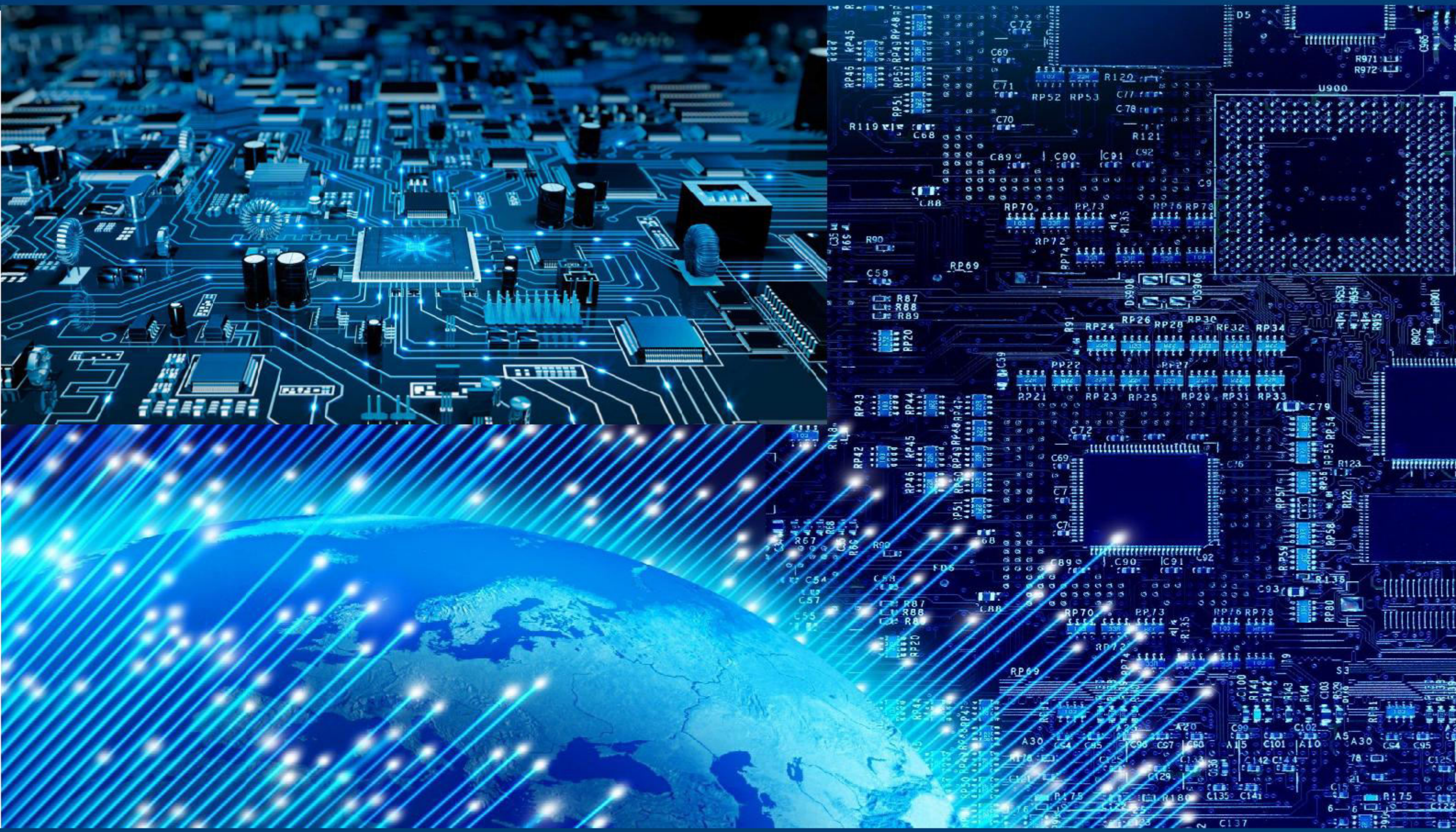

International Journal of Advanced Research in Arts, Science, Engineering & Management (IJARASEM)

| Mobile No: +91-9940572462 | Whatsapp: +91-9940572462 | ijarasem@gmail.com |

www.ijarasem.com